राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी फैसले नीतिगत निर्णय और योजनाएं

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की विधानसभा में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश कर किसानों की उम्मीदों को मजबूती प्रदान की, जिससे उनके चेहरों पर खुशियां लौटी। वहीं राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर उनके भविष्य को सुरक्षित महसूस कराया है। युवा वर्ग के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा हो या फिर 100 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वालों को 50 यूनिट बिजली निशुल्क करने का साहसी इरादा। बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए उनके सपनों को पंख दिये। आम आदमी को संबल दिया गया। बजट पेश करते हुए सदन में अपनी पंक्तियों 'उड़ने के लिए पंख ही नहीं, जज्बा जरूरी है। विश्वास के लिए साधन ही नहीं, हिम्मत और विश्वास भी जरूरी है' को अनुदान मांगों के जवाब और वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर में अपने संबोधन में सही साबित भी कर दिया। अपने वादों और घोषणाओं के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास में पेश 500 से अधिक घोषणाएं में से 100 से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर जनता के दिलों में जगह बनाई और विश्वास जीता। सरकार द्वारा आम जनता से लिये गए सुझावों के बाद पेश यह बजट समुद्र मंथन से निकले अमृत समान साबित होगा।

मौजूदा कार्यकाल का यह चौथा बजट प्रदेश की जनता में जोश, उत्साह, आशा एवं ऊर्जा का संचार करने वाला रहा। शासन की जनता के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता देखने को मिली। इसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला एवं दिव्यांगजन सहित सभी वर्गों के कल्याण की सोच तथा राज्य को समावेशी विकास की प्रतिबद्धता साफ दिखाई दी। साथ ही 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना और 14 नई नगरपालिकाएं बनाने की घोषणा दूरगामी सोच है।

निरोगी राजस्थान में बढ़ते कदम

चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपये का सालाना चिकित्सा बीमा, बोर्न मैरो, ऑर्गनट्रांसप्लांट, बोर्न कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों का नि:शुल्क ईलाज, संभागीय मेडिकल कॉलेजों में 7 सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं, 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय, प्रदेश में 15 चिकित्सालयों का निर्माण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक निशुल्क दुर्घटना बीमा कवर, एक हजार नए उप स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सालयों की क्रमोन्नति, श्रीगंगानगर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ एवं धौलपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू करने सहित कई घोषणाएं कर प्रदेश को निरोगी राजस्थान बनाने के लिए कदम बढ़ाये गये।

आगामी वर्ष में 100 मोहल्ला क्लीनिक की स्थापना होगी। मेडिकल हेल्थ वॉलिंटियर फोर्स का गठन होगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालयों में नेत्र विशेषज्ञों को केरेटोप्लास्टी का प्रशिक्षण दिया जायेगा। पांच हजार कोर्निया कलेक्शन का कार्य होगा। नए उप जिला चिकित्सालय, ट्रोमा सेंटर, आयुर्वेद

औषधालय, होम्योपैथी औषधालय शुरू होंगे। निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने व वर्तमान कॉलेजों के विस्तार और प्रोत्साहन के लिए नई नीति लाई जायेगी। अब फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट स्थापित होगा।

शिक्षा का विस्तार, भविष्य की चमकती तस्वीर

विद्यार्थियों को घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा मिलें, इसके लिए 3820 सैकंडरी विद्यालयों को सीनियर सैकंडरी में क्रमोन्नत किया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, इन स्कूलों के लिए अलग से कैडर और 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा प्रदेश के भविष्य की सुखद तस्वीर बनाती है। वहीं, रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राथमिक विद्यालय, 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय, जयपुर में 100 करोड़ रुपये से इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में सावित्री बाई फूले वाचनालय की स्थापना से शिक्षा का विस्तार और बढ़ेगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्री-प्राइमरी बाल वाटिकाएं शुरू होगी। राजकीय तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में आगामी वर्ष से राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम लागू की जाएगी। साथ ही निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रैगुलेशन एंड फसिलटेशन बोर्ड' का गठन होगा। पांच सौ राजकीय विद्यालयों में नए विषय शुरू होंगे। राइट टू एजुकेशन में निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की 12वीं तक की पढ़ाई में इंदिरा महिला शक्ति निधि से उनकी फीस का पुनर्भरण किया जायेगा। बालिका दूरस्थ बालिका योजना लागू होगी। दो लाख बालिकाओं को 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान' के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण मिलेगा। राजकीय स्कूलों में सप्ताह में दो दिन पाउडर मिल्क का उपयोग होगा। प्रदेश में कई जगहों पर कृषि महाविद्यालय शुरू होंगे।

सामाजिक सुरक्षा से मिली खुशियां

एससी व एसटी विकास कोष की राशि बढ़ाकर 500-500 करोड़ रुपये की गई। सामान्य श्रेणी के ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपये का ईडब्ल्यूएस कोष बनाया गया। प्रदेश में एक हजार इंदिरा रसोई होगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 5 हजार एवं काली बाई भील एवं देवनारायण योजना में 20 हजार स्कूटी का वितरण होगा। जामडोली-जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय शुरू होगा। बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय, निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू, प्रदेश में इंदिरा गांधी मातृत्व योजना लागू की जा रही है। सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास के अंतर्गत 6 छात्रावास शुरू होंगे। लेबर वेलफेयर बोर्ड बनेगा। महाराणा प्रताप आवास अनुदान योजना में राशि अब 70 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये की जा रही है। प्रदेश में 5 हजार नई राशन की दुकानें खुलेंगी। प्रशास शहरों के संग अभियान को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। ऐसे परिवार जिनमें दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग सदस्य ही है, उन्हें सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ देने के लिए 'मुख्यमंत्री-हमारी जिम्मेदारी योजना' शुरू होगी। राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री-मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति शुरू होगी। आरचीएचएस में अब पेंशनर के आश्रित सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

पुलिस और मजबूत, जल्द मिलेगा न्याय

नए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, नवीन पुलिस थाने, नवीन पुलिस चौकियां, एसआई स्तर के पुलिस

थाने सीआई स्तर के थानों में क्रमोन्नत होंगे। वहीं, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, नागौर में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट), सीकर में एनआई एक्ट न्यायालय खोले जायेंगे। इससे लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। अभय कमांड सेंटर, डायल 100, डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन, प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना, तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा 7 पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के भवन का निर्माण कराने की घोषणा की गई। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में नेशनल फोरेंसिक साईंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, गुजरात का ऑफ कैम्पस खोला जायेगा। प्रदेश के उप निरीक्षक स्तर के पुलिस थानों को निरीक्षक स्तर के थानों में क्रमोन्नत किया जायेगा। राज्य में संचालित यात्री वाहनों व एंबुलेंस में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस एवं पैनिक बटन की व्यवस्था शुरू करते हुए कमांड कंट्रोल स्थापित किया जायेगा। लोग ठगी का शिकार नहीं बनें, इसके लिए वित्त विभाग के अधीन 'डायरेक्टरेट ऑफ इकॉनोमी अफेंस' बनाया जायेगा।

जयपुर में बनेगा ई-वेस्ट रिसाइकिल पार्क

50 हजार हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में बॉटनिकल गार्डन, वन्यजीवों को गोद लेने के लिए 'कैपटिव एनीमल स्पॉन्सरशिप स्कीम', ई-वेस्ट के निस्तारण के लिए ई-वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी व जयपुर में ई-वेस्ट रिसाइकिल पार्क की स्थापना होगी। सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को ईको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने के लिए डीपीआर बनाई जायेगी। कोटपूतली, नोखा, केशोरायपाटन, बाड़मेर, बालोतरा, डूंगरपुर, राजसमंद एवं भरतपुर में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज व अन्य कार्य होंगे। शहरों में गीले कचरे को प्रोसेस कर बायोगैस/मिथेन का उत्पादन किया जायेगा।

48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर

छबड़ा तापीय विद्युतगृह का विस्तार, 660-660 मेगावाट की दो इकाईयों की स्थापना, कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार-800 मेगावाट की तीसरी इकाई, गुढ़ा बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना, पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत 48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर, धौलपुर व उदयपुर में 400-400 केवी ग्रिड सब स्टेशन, 132 केवी के 7 जीएसएस एवं 33 केवी के 14 जीएसएस की स्थापना होगी।

कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित

सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस कराने के लिए 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना लागू की गई। एनपीएस को भी एक अप्रेल 2022 को देय वेतन से समाप्त कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न सेवा संवर्गों यथा पुलिस कानिस्टेबल, हैड कानिस्टेबल, जेल प्रहरी, होम गार्ड के आरक्षी, नर्सिंग स्टाफ, आबकारी विभाग के कार्मिकों आदि को देय मैस भत्ते की राशि में 01 अप्रेल, 2022 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर देय

ग्रेच्युटी एवं अवकाशों के बदले नकद भुगतान की गणना उनके सेवानिवृत्ति के समय महंगाई भत्ते की प्रभावी दर से किया जाएगा।

कई देशों में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर

विश्व के कई देशों में राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स शुरू होंगे। 50 हजार नवीन स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लगभग 5.50 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। रिवॉल्विंग फंड एवं कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में 300 करोड़ रुपये तथा बैंकों से ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी। सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर व दौसा जिलों में ग्रामीण हाट एवं सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। आम जन को ई-मित्र के माध्यम से घर के नजदीक 500 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इसमें विस्तार करते हुए निजी क्षेत्र की लगभग 200 अन्य जन उपयोगी सेवाएं यथा ई-कामर्स, ई-शिक्षा, कृषि क्षेत्र एवं चिकित्सा परामर्श आदि भी ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेंगी।

कर प्रस्तावों में भी राहत

बजट 2022-23 में कोई नया कर नहीं लगाया गया। सभी वर्गों को लगभग 1500 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। मोटर वाहन कर, निर्मित या रिक्त आवासीय भूखंडों, रिक्त वाणिज्यिक भूखंडों हकत्याग सहित कई तरह के स्टाम्प ड्यूटी में अलग-अलग छूट प्रदान की है। मद्यसंयम हेतु स्वर्गीय श्री गुरूचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के लिए बजट 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया। इनके अलावा कृषक एवं कृषि आधारित व्यवसायी, उद्योग एवं व्यवसाय, निवेष प्रोत्साहन, एससी-एसटी एवं कमजोर वर्ग के उद्यमियों, रियल एस्टेट, परिवहन, खनन पट्टाधारियों को राहत दी गई है।

सौजन्य से
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान सरकार